



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 10, 2019/पौष 20, 1940

No. 15]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2019/PAUSAH 20, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2019

मामला सं. (निर्णयिक समीक्षा)-21/2018

विषय: चीन जन. गण. से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटरों के आयातों से संबंधित निर्णयिक समीक्षा जांच (एसएसआर) की शुरुआत

1. फा. सं. 7/44/2018-डीजीटीआर.—यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए। दिनांक 1 जुलाई, 2014 के प्रारंभिक जांच परिणाम के आधार पर, प्राधिकारी ने अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिसे वित्त मंत्रालय (एमओए) द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2014 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 40/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा 4 मार्च, 2015 को अंतिम शुल्क की सिफारिश की गई जिसे एमओएफ द्वारा अधिसूचना सं. 11/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 11 अप्रैल, 2015 द्वारा अनंतिम शुल्क लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए लगाया गया था। लगाया गया शुल्क 15 सितम्बर, 2019 को समाप्त हो जाएगा।

2. यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि उससे पहले न हटाया जाए तो उनके लागू होने की तारीख से पाँच वर्षों के बाद वह निष्प्रभावी हो जाते हैं और प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है। उक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है।

3. वर्तमान याचिका मै. आदित्य बिरला इंसुलेटर्स (ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. की एक इकाई), मै. इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी और मै. मार्डर्न इंसुलेटर्स लि. द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाठन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए चीन जन. गण. से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्षों की आगामी अवधि तक लागू रखने के लिए उसकी निर्णयिक समीक्षा की शुरूआत करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

4. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद पूर्ववर्ती जाँच के समान है। विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

'वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद का दायरा ग्लास या पोर्सलेन/सेरामिक के इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, चाहें एसेम्बल्ड हों या अनएसेम्बल्ड। तथापि (क) 1 केवी तक की रेटिंग के बोल्टेज के टेलिफोन या टेलिग्राफ इंसुलेटर्स, (ख) 1 केवी तक की रेटिंग के बोल्टेज के इलेक्ट्रोनिक उपकरण/यंत्र इंसुलेटर, और (ग) कंपोजिट इंसुलेटर वर्तमान जाँच के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्रशिंग्स और बोल्टेज ट्रांसफार्मर विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के दायरे से बाहर हैं।'

5. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अधीन उपशीर्ष सं 8546 और टैरिफ वर्गीकरण के उपशीर्ष 854610 और 854620 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। उत्पाद को परियोजना श्रेणी के आयातों के अध्याय 98 के अधीन भी आयात किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. चूंकि वर्तमान जाँच निर्णयिक समीक्षा जाँच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद पहले सम्पन्न जाँच में यथा परिभाषित उत्पाद के समान रहेगा। मूल जाँच में माप की इकाई एमटी है।

ख. समान वस्तु

7. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीयूसी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के साथ तुलनीय है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता इनका एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।
8. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जाँच में यह निर्धारित किया है कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु समान वस्तु हैं। चूंकि यह समीक्षा जाँच है इसलिए पीयूसी प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती जाँच में निर्धारित वस्तु के समान है। उक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को इस जाँच में भी पाटनरोधी नियमावली के अर्थों के भीतर संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जाना चाहिए।

ग. संबद्ध देश

9. वर्तमान जाँच में शामिल देश जन गणराज्य

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. वर्तमान याचिका मै. आदित्य बिरला इंसुलेटर्स (ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. की एक इकाई), मै. इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी और मै. मार्डर्न इंसुलेटर्स लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा चीन जन. गण. से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा की शुरूआत करने और वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में संगत सूचना उपलब्ध कराई है जिसकी जाँच की शुरूआत पर विचार करने के लिए जाँच की गई है।
11. याचिकाकर्ताओं के अलावा, कुछ अन्य उत्पादक भी हैं जो संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में प्रचालन करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन (**आईईईएमए**) के अनुसार भारतीय उत्पादन का ब्यौरा उपलब्ध कराया है। आईईईएमए विद्युतीय उपकरणों के उत्पादकों की एक एसोसिएशन है और उसके पास देश में उद्योग के दीर्घावधिक हितों की जांच करने के लिए एक पूर्णतः समर्पित इंसुलेटर प्रभाग है।

12. याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 83.88 प्रतिशत है और इसलिए उसे भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनाने वाला माना जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने की अपेक्षित योग्यता रखते हैं और नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

इ. निर्णयिक समीक्षा की शुरुआत

13. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन के जारी रहने और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार समीक्षा करेंगे कि क्या संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू शुल्क को हटाए जाने से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने या घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है और क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के विरुद्ध लागू निश्चयात्मक शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

च. जांच अवधि (पीओआई)

14. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के लिए 01 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2018 तक का प्रस्ताव किया था। हालांकि, प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान जांच कऔर क्षति की जांच अवधि 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान की अवधि के रूप में विचार किया गया है ताकि विल्कुल हाल के आंकड़े प्राप्त किए जा सकें। जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए की जा सकती है।

छ. प्रक्रिया

15. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ज. समय-सीमा

16. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देश में ज्ञात नियातिकों, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना से प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से लिखा गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना ऊपर दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (जिसे प्राधिकारी की वेबसाइट www.dgtr.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है) प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

20. प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातिक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की विक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातिक निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट कर सकते हैं और पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:
- कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, विक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
 - उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।
 - उत्पादक/निर्यातिक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
 - विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।
- ब. गोपनीय/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**
21. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख.), अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। हितबद्ध पक्षों को इस निदेशालय की टीएन 10/2018 दिनांक 7 सितम्बर, 2018 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना अपेक्षित होगा।
22. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
23. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत : सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
26. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
- ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
27. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2019

Subject: Initiation of a Sunset Review investigation (SSR) concerning import of Electrical Insulators from China PR.

F. No. 7/44/2018-DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules). On the basis of Preliminary Findings dated 1st July, 2014, the authority recommended imposition of provisional anti-dumping duties which was imposed vide Custom notification No. 40/2014-customs(ADD) dated 16th September 2014 by Ministry of Finance (MoF). The final duty was recommended on 4th March, 2015 by the authority which was imposed by the MoF vide Notification No. 11/2015-Customs (ADD) dated 11th April, 2015 for a period of five years from the date of provisional duty imposed. The duty imposed would expire on 15th September, 2019.

2. Whereas in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff(Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. The present petition has been filed by M/s Aditya Birla Insulators (A unit of Grasim Industries Ltd.), M/s Insulators and Electricals Company and M/s Modern Insulators Ltd., seeking initiation of sunset review and extension of present anti-dumping duties on imports of ***Electrical Insulators from China PR***, for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the subject goods originating in or exported from China PR.

A. Product Under Consideration (PUC)

4. The product under consideration in the present investigation is same as the previous investigation. The product under consideration is as follows:

“the scope of product under consideration for the purpose of present investigation is electrical insulators of glass or porcelain/ceramic, whether assembled or unassembled. However, (a) telephone or telegraph insulators of voltage rating up to 1 KV, (b) electrical or electronic appliances/device insulators of voltage rating up to 1 KV, and (c) composite insulators are excluded from the scope of present investigation. Further, it is clarified that bushings and voltage transformers are beyond the scope of the product under consideration and proposed measures.”

5. Subject goods are classified under chapter 85 of Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 8546 and subheading 854610 and 854620 of the Tariff Classification. The product has also been imported

- under chapter 98 under project category imports. The custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.
6. The investigation being a sunset review investigation, PUC remains the same as defined in the previously concluded investigation. The unit of measurement is MT as in the original investigation.

B. Like Article

7. Petitioners have claimed that there is no known difference in the product produced by the petitioner and exported from the subject country. The PUC produced by the domestic industry are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods with the subject goods imported from the subject country. The goods produced by the petitioners are technically and commercially substitutable with goods imported from the subject countries. The consumers are using the two interchangeably.
8. The Designated Authority has determined in the previous investigations that the subject goods imported from subject countries and the one produced by the domestic industry are like article. Since this being the review investigations, the PUC is the same as the one determined by the Authority in the previous investigations. In view of the above, the subject goods produced by the petitioners should be treated as a like article to the goods imported from the subject country within the meaning of the Anti-dumping Rules for this investigation as well.

C. Subject countries

9. The country involved in the present investigation is China PR.

D. Domestic Industry & Standing

10. The present petition has been filed by M/s Aditya Birla Insulators (A unit of Grasim Industries Ltd.), M/s. Insulators and Electricals Company and M/s. Modern Insulators Ltd., and (herein after referred as petitioners) seeking initiation of sunset review and extension of present anti-dumping duties on imports of **Electrical Insulators from China PR**. The petitioners have provided relevant information in the petition which has been examined for consideration of initiation.
11. Apart from the petitioners, there are some other producers who operate in both organised and unorganised sector. The petitioners have provided the details of Indian production as per **Indian Electrical & Electronics Manufacturers' Association (IEEMA)**. IEEMA is an association of electrical equipment producers and has a fully dedicated insulator division to look into the long-term interests of the industry in the Country.
12. Production by Petitioners constitute 83.88% of Indian production and therefore may be considered as constituting major proportion in the Indian production. The petitioners therefore satisfy the requirement of standing to file the present petition and constitute "Domestic Industry" within the meaning of the Rules.

E. Initiation of Sunset Review Investigation

13. Having satisfied itself, on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury, the Authority hereby initiates an investigation in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of Anti-dumping Rules, to review whether revocation of the duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, shall lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods from the subject countries and continuation or recurrence of injury to the domestic industry, and need for continued imposition of the definitive duty in force against the subject goods originating in or exported from the subject countries.

F. Period of Investigation (POI)

14. The petitioner had proposed POI from 1st April 2017 to 30th June 2018. However, the Authority has decided that the period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2017 to 30th September 2018 (18 months) with a view to obtain most recent data and the injury investigation period

has been considered as the period 2014-15, 2015-16, and 2016-17. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

G. Procedure

15. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 & 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

H. Time Limit

16. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned below not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.
17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose the antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

I. Submission of Information

18. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address :

**The Director General,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi -110001.**

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the authority at www.dgtr.gov.in within the time limit set out above. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.
20. While submitting questionnaire response, producer/ exporter may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production and sale of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:
 - a. Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signal reflecting supply and demand and without significant state interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
 - b. Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
 - c. The producers/exporters are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
 - d. Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

J. Submission of Information on Confidential/Non-confidential Basis

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of

- each page. The interested parties are required to follow guidelines contained in TN 10/2018 dated 7th September, 2018 of this Directorate.
22. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two(2) copies of the confidential version and of the non-.confidential version must be submitted by all the interested parties.
 23. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such Information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
 24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
 25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
 26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

K. Inspection of Public File

27. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

L. Non-Cooperation

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General